उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

6641. **श्री गंगाभक्त सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ जिले चुने गये हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के 13 जिले सम्मिलित हैं और इन तेरह जिलों में केवल तीन पिछड़े जिले हैं जबकि राज्य में पिछड़े जिलो की सख्या 39 है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जिले किन-किन राज्यो से चुने गये है,

(ग) उनके चयन के लिये क्या मापदंड अपनाया गया, और

(घ) उत्तर प्रदेश के सभी 39 पिछड़े जिलो को सम्मिलित न करने के क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मायती) : (क) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम की केन्द्र प्रायोजित योजना देश के 112 जिलो मे क्रियान्वित की जा रही है जिसमे उत्तर प्रदेश के 13 जिले भी शामिल हैं। इन 13 जिलो में मे 11 पिछड़े जिले हैं।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के सभी 22 राज्यों को ले लिया गया है।

(ग) और (घ). ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम के अधीन 1962-63 में चुनाव करने के लिये निम्नलिखित कसौटी अपनाई गई थी :—

(1) जहां कृषि सम्बन्धी स्थिति अनुकूल है और उल्लेखनीय कृषि परक प्रयास किये जा रहे हैं और इसके साथ ही जहां जनसख्या का भारी दबाव है।

(2) जहां पर कृषि प्रमुख रूप से बिना सिंचाई की स्थितियों में की जाती है और जहां पर अतिरिक्त रोजगार की पर्याप्त आवश्यकता है।

(3) जहां अनुकूल प्राकृतिक स्थितियों और विकास संसाधनों के विकास के अभाव में बहुत अधिक बेकारी है।

(4) जनजातीय और अन्य पिछड़े क्षेत्र।

(5) वे क्षेत्र जिनमें बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं अथवा स्थापित की जा रही हैं ताकि समन्वित औद्योगिक ग्रामीण विकास किया जा सके तथा जिनमें औद्योगिक परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि और छोटे उद्योगो को साथ-साथ विकसित किया जा रहा है ; और

(6) ग्रामीण विश्वविद्यालयो और संस्थाओं के निकटवर्ती क्षेत्र।

पाचवी पंचवर्षीय योजनावधि में, ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओ का विस्तार करने के लिए यह निश्चय किया गया था कि विभिन्न राज्यों के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों मे से जिलो का चयन किया जाना चाहिए।

शुरू में ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम के लिये केवल 45 परियोजनाएं हाथ में ली गई थी और इन्हे विभिन्न राज्यो को आबंटित कर दिया गया था। चार और परियोजनाएं और बढ़ाई गई थी जिन्हे भिलाई, रांची, दुर्गापुर आदि औद्योगिक बस्तियो के इर्द-गिर्द स्थापित किया जाना था। पांच और परियोजनाएं हाथ में ली गई थी एक नवनिर्मित हरियाणा राज्य के लिए थी और चार अन्य आसपास की अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं थीं। 1970 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए 50 और परियोजनाएं हाथ में लेने का निर्णय किया गया था जिनका देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों से चयन किया जाना था। किन्तु पांचवीं योजनावधि में परियोजनाओं की सख्या बढ़ाकर

87 कर दी गई थी और देश की कुल परियोजनाओं की संख्या 112 हो गई थी।

Promotion of Senior Assistance

6642 SHRI VINAYAK PRASAD YADAV Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state

(a) whether it is a fact that senior Assistants who fulfil certain conditions are allowed one additional increment on the basis of their Confidential Reports,

(b) whether it is also a fact that Assistants are allowed to cross Efficiency Bar and are also promoted to officiate as Section Officers on the basis of 'Good Reports but they are not eligible for the additional increment on Good Reports and

(c) if so whether Government will allow additional increment on the basis of 'Good' reports if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S D PATIL) (a) No Sir

(b) Crossing of the Efficiency Bar s allowed by the Competent authority on an overall assessment of the Reports Promotion to Section Officers Grade are made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit

(c) Does not arise in view of (a) above

Applications for licence for manufacture of air-break equipment by Westinghouse Saxby Farmer Ltd

6643 SHRI SOMNATH CHATTERJEE Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) whether the management of Westinghouse Saxby Farmer Ltd, a public sector undertaking applied for licence for manufacture of air-break equipment for railway rolling stock,

(b) if so, whether Government have imposed pre-condition of export obligations;

(c) whether the company has represented for issue of a formal licence without any pre-condition, and

(d) if so, decision taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) (a) to (c) Yes Sir

(d The matter is under further consideration and a decision is expected to be taken shortly

Compulsory retirement of Employees

6644 SHRI A BALA PAJANOR Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state

(a) the number of Central Government officers compulsorily retired during the last 10 months as a penalty, and the reasons therefor,

(b) the number of officers who were given 3 months notice of retirement under the Rules and prematurely retired and

(c) whether Government give an opportunity to officers before giving notice of premature retirement regarding the grounds on which they have been marked out for such retirement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S D PATIL) (a) and (b) The information is not readily available It will be collected and placed on the Table of the House as soon as possible

(c) Un-like compulsory retirement premature retirement is not a penalty and is only an administrative action As such the question of giving opportunity of defence to an employee who is to be prematurely retired does not arise

देश में भारी उद्योग

6645. श्री छविराम अर्गल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में भारी उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां